



# Daily करेंट अफेयर्स

»» 03 जुलाई 2025

## NATIONAL AFFAIRS

### 1. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने 'ZET' अपनाने और इसके पर्यावरण-ऊर्जा प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की।



जुलाई 2025 में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने नई दिल्ली में 'भारत में ZET को अपनाना और उत्सर्जन और ऊर्जा पर इसका प्रभाव (जून 2025)' शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट का अनावरण किया। रिपोर्ट में भारत की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए शून्य-उत्सर्जन ट्रकिंग (ZET) को अपनाने में तेजी लाने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया है।

- रिपोर्ट में जीरो-एमिशन ट्रकिंग (ZET) में बदलाव को गति देने में सहायक सार्वजनिक नीति की भूमिका पर गंभीरता से जोर दिया गया है, तथा इसे भारत के माल ढुलाई क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए एक परिवर्तनकारी समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बदलाव राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने और कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

- रिपोर्ट का एक मुख्य भाग भारत के मध्यम और भारी-ड्यूटी ट्रक (M&HDT) खंड पर केंद्रित है, जो बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक (BET) की ओर बदलाव की वकालत करता है। इस बदलाव से देश के सबसे अधिक ऊर्जा-गहन परिवहन क्षेत्रों में से एक में

जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आने का अनुमान है।

- रिपोर्ट में ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए ZET को अपनाने को एक शक्तिशाली लीवर के रूप में पहचाना गया है। यह इस संक्रमण से होने वाले पर्यावरणीय लाभों पर भी जोर देता है, जिसमें बेहतर वायु गुणवत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं।

#### Key Points:-

(i) उद्योगों, नीति संस्थानों और अनुसंधान निकायों के हितधारकों को शामिल करते हुए एक वर्ष के अध्ययन के माध्यम से संकलित, रिपोर्ट में गहन परिदृश्य विश्लेषण शामिल हैं, जो भारत के माल विद्युतीकरण के मार्गों पर स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

(ii) भारत का माल परिवहन मुख्य रूप से M&HDT क्षेत्र द्वारा संचालित है, जो लगभग 70% लॉजिस्टिक्स परिवहन को संभालता है। यह क्षेत्र देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, फिर भी यह परिवहन-संबंधी उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत भी है।

(iii) अपने आर्थिक महत्व के बावजूद, M&HDT क्षेत्र भारत के परिवहन क्षेत्र में ईंधन की खपत का लगभग 40% हिस्सा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जब तक तेजी से बदलाव नहीं किया जाता, तब तक यह क्षेत्र भारत के उत्सर्जन पदचिह्न का एक बड़ा हिस्सा चलाता रहेगा, जिससे राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्य कमजोर पड़ेंगे।

### 2. केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म C-FLOOD लॉन्च किया।



2 जुलाई, 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में C-FLOOD (केंद्रीकृत बाढ़ पूर्वानुमान और जलप्लावन मॉडलिंग प्रणाली) का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान मंच है जो 48 घंटे पहले तक गांव-स्तर पर अलर्ट प्रदान करता है, जिससे देश की प्रारंभिक चेतावनी और आपदा तैयारी की क्षमता बढ़ जाती है।

- C-FLOOD गांव स्तर पर वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान और जल-स्तर की चेतावनी तैयार करता है। अति स्थानीय सटीकता के लिए डिज़ाइन किया गया, यह जिला अधिकारियों, आपदा एजेंसियों और समुदायों को स्थान-विशिष्ट चेतावनियों के साथ सहायता करता है, जिससे भारत अपने बाढ़ प्रबंधन बुनियादी ढांचे में पूर्वानुमान की इस सटीकता को लागू करने वाला पहला देश बन गया है।

- वर्तमान में, यह प्रणाली महानदी, गोदावरी और तापी बेसिन को कवर करती है। यह राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत उन्नत 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडल का उपयोग करके CWC (केंद्रीय जल आयोग), C-DAC (उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र) पुणे, NRSC (राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र) और विभिन्न राज्य सिंचाई विभागों जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों से डेटा एकत्र करता है।

- C-FLOOD के सिमुलेशन उपग्रह-आधारित स्थलाकृतिक मानचित्रों, वर्षा टेलीमेट्री और

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEMs) द्वारा संचालित होते हैं। ये प्रति घंटे अपडेट और 48 घंटे के रंग-कोडित बाढ़ अलर्ट को सक्षम करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय इन पूर्वानुमानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (NDEM) से जोड़ने की योजना बना रहा है ताकि सभी क्षेत्रों में कुशल आपातकालीन समन्वय हो सके।

#### Key Points:-

(i) लॉन्च के दौरान, मंत्री सी.आर. पाटिल ने जागरूकता और स्थानीय भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने जिला कलेक्टरों और आपदा टीमों से सार्वजनिक सलाह में सी-फ्लड पूर्वानुमानों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने आगामी प्रशिक्षण मॉड्यूल, पंचायत-स्तरीय कार्यशालाओं और मॉक ड्रिल की भी घोषणा की, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी अंतिम-मील आपदा तैयारी और संस्थागत क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) MoJS (जल शक्ति मंत्रालय), CWC, NRSC, IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) और NDMA (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अधिकारी इस लॉन्च में शामिल हुए। C-FLOOD जलवायु लचीलेपन का समर्थन करता है और डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे और स्मार्ट सिटीज जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ जुड़ता है, जिससे बाढ़ प्रतिक्रिया, योजना और संसाधन संरक्षण में सुधार होता है।

(iii) जल शक्ति मंत्रालय ने दिसंबर 2025 तक गंगा, यमुना, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र सहित सभी प्रमुख घाटियों में C-FLOOD का विस्तार करने की योजना बनाई है। भविष्य के लक्ष्यों में राष्ट्रव्यापी पंचायत-स्तरीय अलर्ट, क्षेत्र सत्यापन और स्वचालित ट्रिगर्स का उपयोग करके जिला आपदा पोर्टलों के साथ एकीकरण शामिल है, जिससे पूरे भारत में मजबूत समुदाय-संचालित बाढ़ पूर्वानुमान और जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित हो सके।

### 3. समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए चेन्नई में प्रथम आसियान-भारत क्रूज वार्ता 2025 का उद्घाटन किया गया।



जून 2025 में, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के प्रमुख केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई, तमिलनाडु में पहली आसियान-भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। यह वार्ता भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संबंधों और क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक और पर्यटन मील का पत्थर साबित हुई।

- इस संवाद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया और Laos PDR के साथ-साथ तिमोर लेस्ते सहित सभी दस आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) देशों के 30 से अधिक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बंगाल की खाड़ी और इंडो-पैसिफिक समुद्री जुड़ाव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- 2015 में शुरू की गई सागर माला पहल के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 5,000 किलोमीटर नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग का विस्तार करना है।

- क्षेत्रीय समुद्री पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बंदरगाह बुनियादी ढांचे, यात्री टर्मिनलों और जल-आधारित परिवहन प्रणालियों के

माध्यम से आसियान देशों के साथ क्रूज कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

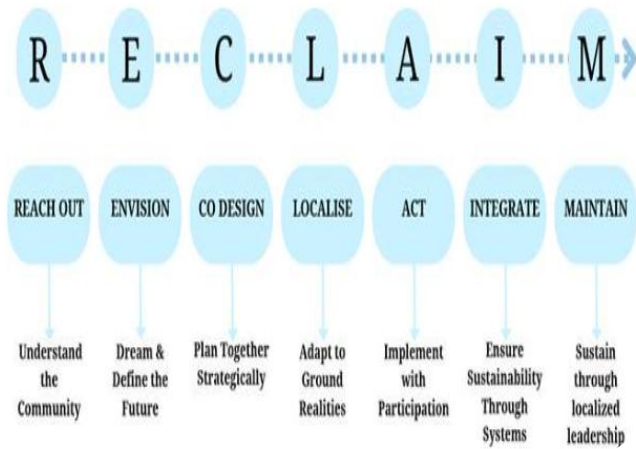
#### Key Points:-

(i) क्रूज संवाद में सतत पर्यटन, बंदरगाह आधारित विकास और सीमा पार क्रूज सर्किट में सहयोग पर प्रकाश डाला गया। सत्रों में निवेश के अवसरों, क्रूज मार्ग डिजाइन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में नए पर्यटक सर्किटों पर चर्चा की गई, ताकि भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री मार्गों में विरासत स्थलों को जोड़ा जा सके।

(ii) इस मंच ने नीतिगत ढाँचों, बुनियादी ढाँचे की योजना और विनियामक प्रक्रियाओं को संरेखित करने का काम किया। प्रतिनिधियों ने बंदरगाह प्रबंधन, क्रूज जहाज संचालन और यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा सुविधा पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। चर्चाओं में टर्मिनलों को उन्नत करने, विनियमों को मानकीकृत करने और बेहतर कनेक्टिविटी और सेवाओं के माध्यम से अधिक क्रूज लाइनों को आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया।

(iii) सरकार ने 2029 तक प्रतिवर्ष 1 मिलियन क्रूज यात्रियों तक पहुंचने का लक्ष्य घोषित किया है, जो 2025 में केवल 14,000 से काफी अधिक है। आधुनिक बंदरगाहों, बेहतर पर्यटन बुनियादी ढांचे और आसियान देशों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन केंद्र बनाने के लिए जहाजों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

### 4. कोयला मंत्रालय सतत खदान बंदी के लिए RECLAIM फ्रेमवर्क शुरू करेगा।



4 जुलाई, 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी.किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक समारोह में रिक्लेम (RECLAIM) लॉन्च किया, जो एक अभिनव खदान बंद करने का ढाँचा है। इसका नाम है रीच-आउट, एनविज़न, को-डिज़ाइन, लोकलाइज़, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साथ कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन द्वारा विकसित RECLAIM समुदाय-संचालित और टिकाऊ खदान बंद करने और बंद होने के बाद की योजना पर केंद्रित है।

- RECLAIM खदान बंद होने और पुनः उपयोग के चरणों के दौरान सामुदायिक सहभागिता को शामिल करने के लिए सात-चरणीय रोडमैप प्रदान करता है। यह निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी को औपचारिक बनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि खनन से प्रभावित आबादी को भूमि पुनर्प्राप्ति, आजीविका बहाली और पारिस्थितिक उपचार में अपनी बात रखने का अधिकार है, जिससे प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और सामाजिक समानता दोनों को मज़बूती मिलती है।

- यह ढांचा लैंगिक समावेशन और कमजोर समूहों के प्रतिनिधित्व पर ज़ोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों को योजना में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। यह अपनी प्रक्रियाओं को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ता है, जिससे समापन प्रक्रिया में

स्थानीय शासन और जवाबदेही को मज़बूती मिलती है।

#### Key Points:-

(i) RECLAIM भारत के विविध खनन संदर्भों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए व्यावहारिक उपकरणों, टेम्पलेट्स और क्षेत्र-परीक्षणित विधियों का एक सेट प्रदान करता है। प्राथमिकताओं में पारिस्थितिकी बहाली शामिल है - जैसे वनरोपण, जल स्तर का कायाकल्प, और पुरानी खदानों को इको-पार्क या कृषि भूमि में बदलना - इस प्रकार बंद खदानों को स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों में बदलना।

(ii) यह ढांचा वैकल्पिक आजीविका के विकास, कौशल निर्माण, क्षमता विकास और आय सृजन पहलों को बढ़ावा देने का समर्थन करता है ताकि समुदायों की खनन पर निर्भरता कम हो सके। यह उचित परिवर्तन कोयला-निर्भर क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण के लिए खदान बंद करने को अवसर में बदलने के उद्देश्य को रेखांकित करता है।

(iii) कोयला मंत्रालय द्वारा समर्थित, RECLAIM जिम्मेदारी से खदान बंद करने में राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित है। स्थिरता, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय सुधार को एकीकृत करके, यह भारत के जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों और चरणबद्ध समाप्ति का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए न्यायोचित परिवर्तन एजेंडे का पूरक है।

5. PM-MITRA योजना के तहत विरुधुनगर को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में चुना गया, ₹1,900 करोड़ पार्क को मंजूरी दी गई।



जुलाई 2025 में, मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में पीएम-मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। 1,052 एकड़ में फैला यह पार्क तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता बनने के भारत के अभियान में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

- PM-MITRA पार्क में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जिसमें 13 लाख वर्ग फुट के प्लग-एंड-प्ले यूनिट्स, 10,000 श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं, और शून्य तरल अपशिष्ट प्रणाली जैसे 15 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा 5 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल होंगे। इसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्स्टाइल उत्पादन को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है।

- ₹10,000 करोड़ के करीब संयुक्त निवेश लक्ष्य के साथ, इस पार्क से लगभग 100,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने और तमिलनाडु के कपड़ा क्षेत्र में ₹19,000 करोड़ के कुल निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।

#### Key Points:-

(i) विरुधुनगर पार्क की स्थापना से कपड़ा मूल्य श्रृंखला को समेकित किया जाएगा - कटाई और बुनाई

से लेकर प्रसंस्करण और परिधान निर्माण तक - सभी एक ही स्थान पर। तमिलनाडु के SIPCOT के तहत विकसित इस पार्क में नवाचार और दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण सुविधाएं और सहायता सेवाएं भी शामिल होंगी।

(ii) निर्माण कार्य सितंबर 2026 तक पूरा होने वाला है, जिसकी योजना CM एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग पर आधारित है। स्थानीय अधिकारी इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम और सरकार के दोनों स्तरों द्वारा "लगातार अनुवर्ती कार्रवाई" के रूप में वर्णित करते हैं।

(iii) विरुधुनगर भारत भर में चुने गए सात PM-MITRA पार्कों में से एक है - गुजरात, कर्नाटक, UP, MP, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में। सामूहिक रूप से, इन पार्कों से ₹70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित होने और 200,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे भारत की स्थिति एक प्रमुख वैश्विक कपड़ा निर्यातक के रूप में मजबूत होगी।

6. बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी किया जाएगा, विस्तार के लिए 123.5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।



जुलाई 2025 में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी करने को मंजूरी दी।

- यह सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री के बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से बेंगलुरु के शहरी और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है।

- यह निर्णय डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा बेंगलुरु के प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचे, जैसे बेंगलुरु मेट्रो, एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है, जिन्हें यूपीए सरकार के तहत 2004 से 2014 के बीच प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अनुमोदित या कार्यान्वित किया गया था।

#### Key Points:-

(i) कर्नाटक सरकार ने विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के चरण-2 के विकास के लिए 123.5 करोड़ रुपये के वित्त पोषण को भी मंजूरी दी, जिसमें उच्च शिक्षा सुधार के लिए NEP 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) लक्ष्यों के अनुरूप नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, उन्नत कक्षाएं, हरित स्थान और डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल होगा।

(ii) नाम बदलने को समावेशी आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने, भारत के वैश्विक IT पदचिह्न को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की शुरुआत में बेंगलुरु को विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने में मदद करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने में डॉ. सिंह की विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाता है।

(iii) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा औपचारिक रूप दिए जाने के बाद, नाम बदलने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के अभिलेखों और शैक्षणिक दस्तावेजों में दिखाई देगी। इसे एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में भी देखा

जाता है जो दूरदर्शी शासन के महत्व को पुष्ट करता है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव को स्वीकार करता है।

## BANKING & FINANCE

1. SBI ने 70वीं वर्षगांठ पर FY27 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना बनाई।



1 जुलाई, 2025 को, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान एक प्रमुख हरित ऊर्जा पहल का अनावरण करके अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाई। बैंक ने भारत के अक्षय ऊर्जा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में योगदान देने के लिए अपने महत्वाकांक्षी सोलर रूफटॉप कार्यक्रम की घोषणा की।

- इस नई पहल के तहत, SBI ने वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) तक पूरे भारत में 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से लैस करने की योजना बनाई है।

- यह कार्यक्रम घरेलू स्तर पर छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को अपनाने में सहायता करेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती, टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ेगी।

#### Key Points:-

(i) SBI की सौर योजना 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है और PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक है। यह भारत की हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव के हिस्से के रूप में स्थानीय उद्यमिता और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है।

(ii) सौर ऊर्जा के साथ-साथ, SBI ने वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत कावेरी नदी बेसिन में 9 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। यह अभियान पारिस्थितिकी बहाली पर केंद्रित है और इससे वंचित छात्रों और विकलांग लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा, जिससे बैंक के सामाजिक उत्तरदायित्व मिशन को बल मिलेगा।

(iii) बैंक ने अक्षय ऊर्जा (RE), ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना की भी घोषणा की है - यह कदम SBI को भारत के हरित परिवर्तन में एक प्रमुख वित्तीय उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

## 2. RBI 2026 से एमएसई के लिए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी पर प्रतिबंध लगाएगा।



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2026 से बैंकों और NBFCs को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को दिए गए 7.5 करोड़ रुपये तक के फ्लोटिंग-रेट ऋणों पर पूर्व भुगतान या फौजदारी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।

● 6 अक्टूबर, 2024 को आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को 1 जनवरी, 2026 से फ्लोटिंग-रेट ऋणों पर फौजदारी और पूर्व भुगतान दंड से छूट देकर व्यक्तियों के समान सुरक्षा प्राप्त होगी। यह सुधार एक समान उधारकर्ता अधिकार सुनिश्चित करता है।

● RBI ने 21 फरवरी, 2025 को एक मसौदा परिपत्र जारी किया, जिसमें 21 मार्च, 2025 तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। मसौदे में प्रस्ताव है कि बैंकों, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसी सभी विनियमित संस्थाओं (RE) को MSEs और व्यक्तियों के लिए बिना किसी शुल्क के पूर्व भुगतान की अनुमति देनी चाहिए, जिससे ऋण प्रक्रिया में लचीलापन और पारदर्शिता बढ़ेगी।

● यह छूट MSEs को दिए गए सभी फ्लोटिंग-रेट ऋणों पर लागू होगी, जो MSMED अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित 7.5 करोड़ रुपये की कुल ऋण सीमा तक है। यह नियम पुनर्भुगतान के स्रोत की परवाह किए बिना व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों उद्देश्यों को कवर करता है, जिससे आसान पुनर्वित्त और बेहतर ऋण शर्तें संभव हो जाती हैं।

### Key Points:-

(i) RBI के पर्यवेक्षी निष्कर्षों से पता चला है कि कई ऋणदाताओं ने छिपे हुए या प्रतिबंधात्मक खंड लगाए हैं जो एमएसई को बेहतर ऋणदाताओं के पास जाने से हतोत्साहित करते हैं। इस नीति सुधार का उद्देश्य ऐसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को खत्म करना और उधारकर्ताओं को योग्यता, मूल्य निर्धारण और सेवा

की गुणवत्ता के आधार पर ऋण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।

(ii) अब ऋणदाताओं को ऋण स्वीकृति के समय प्रदान किए गए मुख्य तथ्य विवरण (KFS) में पूर्व भुगतान और फौजदारी से संबंधित सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना आवश्यक होगा। उन्हें ऋणदाता द्वारा शुरू की गई घटनाओं जैसे कि ऋण वापसी या पुनर्गठन के कारण पूर्वव्यापी शुल्क या दंड लगाने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

(iii) यह पहल भारत के व्यापार करने में आसानी के एजेंडे का समर्थन करती है और MSME क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा स्वागत किए जाने से उम्मीद है कि इससे ऋण की लागत कम होगी और देश भर में एमएसई की सेवा करने वाले ऋणदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों को बढ़ावा मिलेगा।

### 3. RBI ने बैंकों को साइबर सुरक्षा के लिए दूरसंचार विभाग के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक को अपनाने का आदेश दिया।



30 जून, 2025 से, RBI ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को API के माध्यम से दूरसंचार विभाग के वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) को एकीकृत करने

का निर्देश दिया है, जिससे वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

- 30 जून, 2025 को जारी RBI की सलाह के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और सहकारी बैंकों को दूरसंचार विभाग की FRI प्रणाली को अपने धोखाधड़ी प्रबंधन ढांचे में एकीकृत करना होगा, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल मोबाइल नंबरों का वास्तविक समय वर्गीकरण संभव हो सके - मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में टैग किया जा सके।

- मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया, FRI बहुआयामी विश्लेषण के आधार पर मोबाइल नंबरों को वर्गीकृत करने के लिए I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, दूरसंचार विभाग के चक्षु प्लेटफॉर्म, मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूचियों और वित्तीय संस्थानों सहित कई स्रोतों से खुफिया जानकारी एकत्र करता है।

- RBI ने दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ API-आधारित एकीकरण पर जोर दिया, जिससे बैंकों और UPI खिलाड़ियों को संदिग्ध लेनदेन को अस्वीकार करने, देरी करने या सत्यापन के लिए चिह्नित करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे UPI प्रणाली में उपभोक्ता संरक्षण मजबूत हो, जिससे अप्रैल 2025 में औसतन 596 मिलियन दैनिक लेनदेन हुए।

#### Key Points:-

(i) फोनपे, PNB, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम, गूगल पे और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसे शुरुआती अपनाने वालों ने पहले ही एफआरआई को एकीकृत कर लिया है, इसका उपयोग “बहुत उच्च” जोखिम वाले नंबरों से लेनदेन को रोकने और “मध्यम” जोखिम वाले लोगों पर अलर्ट जारी करने के लिए किया है, जो

पूर्वानुमान की सटीकता और जोखिम न्यूनीकरण को दर्शाता है।

(ii) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने RBI के इस कदम को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम में एक "महत्वपूर्ण क्षण" बताया और दूरसंचार-वित्तीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला, तथा समय के साथ धोखाधड़ी-जोखिम मॉडलिंग को परिष्कृत करने के लिए निरंतर फीडबैक लूप की क्षमता पर ध्यान दिया।

(iii) RBI का यह आदेश व्यापक साइबर सुरक्षा नीति दिशा के अनुरूप है, जिसमें RBI का शून्य-विश्वास और AI-जागरूक रक्षा दृष्टिकोण शामिल है, जैसा कि हाल ही में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से तीसरे पक्ष की निगरानी और सक्रिय धोखाधड़ी रोकथाम प्रणालियों को बढ़ाने का आग्रह करते हुए दोहराया है।

#### 4. इंडसइंड बैंक ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए 'INDIE फॉर बिजनेस' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।



जुलाई 2025 में, इंडसइंड बैंक ने 'INDIE फॉर बिजनेस' लॉन्च किया, जो एक समर्पित डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत के 60+ मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना है, जिसमें अगले तीन वर्षों में MSME राजस्व को बढ़ावा देने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

● मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, प्लेटफॉर्म 'INDIE फॉर बिजनेस' इंडसइंड बैंक की व्यापक डिजिटल इनोवेशन रणनीति और MSMEs विकास रोडमैप का हिस्सा है। यह MSMEs के लिए भुगतान, संग्रह, ऋण, कर भुगतान और खाता प्रबंधन को कवर करने वाला एक ऑल-इन-वन इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक MSME राजस्व को दोगुना करना है।

● INDIE फॉर बिजनेस में कई उद्योग-प्रथम विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें सभी व्यावसायिक खातों का 360-डिग्री समेकित दृश्य, ऋण शेष राशि, ईएमआई और देय तिथियों की वास्तविक समय ट्रैकिंग शामिल है। यह कई व्यावसायिक संस्थाओं को संभालने वाले उद्यमियों के लिए प्रोफ़ाइल स्विचिंग का भी समर्थन करता है, जिससे बहु-खाता वित्तीय संचालन पर नियंत्रण और दृश्यता में सुधार होता है।

● यह प्लेटफॉर्म विक्रेता चालान और कर्मचारी वेतन के लिए थोक भुगतान को सक्षम करके निर्बाध वित्तीय संचालन का समर्थन करता है। यह माल और सेवा कर (GST), आयकर और सीमा शुल्क जैसे वैधानिक बकाया के डिजिटल भुगतान की भी अनुमति देता है - जिससे यह MSME के लिए विनियामक और वित्तीय अनुपालन के लिए एक एकीकृत गंतव्य बन जाता है।

#### Key Points:-

(i) MSME ऑनबोर्डिंग को सरल बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिजिटल, कागज़ रहित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है। व्यवसाय आधार-आधारित सत्यापन, डेबिट कार्ड प्रमाणीकरण या इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके तुरंत ऑनबोर्ड हो सकते हैं। यह स्व-सेवा डिजिटल दृष्टिकोण मैनुअल कागज़ात और भौतिक शाखा यात्राओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) ऑनबोर्डिंग के बाद, MSMEs को भुगतान स्वीकृति विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच प्राप्त होती है, जिसमें पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) टर्मिनल, QR कोड और डिजिटल भुगतान लिंक शामिल हैं। इन उपकरणों का उद्देश्य राजस्व संग्रह को बढ़ाना, सुचारू लेनदेन को सक्षम करना और MSMEs को उनके पैमाने या क्षेत्र की परवाह किए बिना डिजिटल समाधान प्रदान करना है।

(iii) यह प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगे MSMEs को तेज़, कागज़ रहित समाधान प्रदान करके सीमा पार भुगतान की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। 'INDIE फॉर बिज़नेस' के साथ, इंडसैंड बैंक सुविधा, अनुपालन और मापनीयता को एक सुरक्षित इंटरफ़ेस में जोड़कर MSMEs सेगमेंट में खुद को डिजिटल बैंकिंग लीडर के रूप में स्थापित करना चाहता है।

## 5. स्लाइस ने बेंगलुरु में भारत की पहली UPI-संचालित बैंक शाखा शुरू की।



जून 2025 के अंत में, फिनटेक फर्म स्लाइस, जिसका हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय हुआ है, ने डिजिटल बैंकिंग और क्रेडिट पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अपने UPI क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ कोरमंगला, बेंगलुरु में भारत की पहली UPI-केंद्रित भौतिक बैंक शाखा और ATM लॉन्च किया।

● बेंगलुरु में कोरमंगला शाखा में प्रत्येक ग्राहक टचपॉइंट पर पूर्ण UPI एकीकरण की सुविधा है, जिसमें तत्काल खाता खोलने के लिए कियोस्क और एक UPI-सक्षम ATM शामिल है जो केवल QR कोड को स्कैन करके नकद जमा और निकासी की अनुमति देता है - किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

● स्लाइस ने इसके साथ ही अपना प्रमुख UPI क्रेडिट कार्ड, "स्लाइस सुपर कार्ड" भी लॉन्च किया है, जिसमें शून्य ज्वाइनिंग या वार्षिक शुल्क, सभी खरीद पर 3% तक कैशबैक और "स्लाइस इन 3" सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को लेनदेन को तीन ब्याज मुक्त किश्तों में बदलने की अनुमति देता है।

### Key Points:-

(i) नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के बाद एक पूर्ण-स्टैक बैंक के रूप में, स्लाइस अपने संपूर्ण बैंकिंग बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करता है - कोर सिस्टम से लेकर अंडरराइटिंग तक - जिसका लक्ष्य 200 मिलियन से अधिक वंचित डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से ऋण का लोकतंत्रीकरण करना है।

(ii) स्लाइस के CEO सतीश कुमार कालरा ने इस बात पर जोर दिया कि बिक्री केन्द्रों और बैंकिंग में UPI को एकीकृत करने से ऋण पहुंच में बदलाव आएगा: "UPI पर ऋण अगली बड़ी छलांग होगी", जिसका लक्ष्य 300 मिलियन नए उपयोगकर्ता हैं और निर्बाध, सुरक्षित और समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

## ECONOMY & BUSINESS

1. जियो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) प्रदाता बन गया।



जून 2025 में, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ग्राहक आधार के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) प्रदाता बन जाएगा, जो टी-मोबाइल और एयरटेल से आगे निकल जाएगा, जो भारत के ब्रॉडबैंड परिदृश्य में जियो एयरफाइबर विस्तार और मजबूत ग्रामीण पैठ रणनीति द्वारा संचालित होगा।

- मई 2025 तक, अल्ट्रा ब्रॉडबैंड राउटर (UBR) उपयोगकर्ताओं सहित जियो के कुल फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) ग्राहक आधार 6.88 मिलियन तक पहुँच गया, जो वैश्विक स्तर पर T-मोबाइल के 6.85 मिलियन से अधिक है। ICICI सिक्योरिटीज और इंफॉर्मा टेक डेटा के अनुसार, यह जियो को ग्राहक संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा FWA प्रदाता बनाता है।

- अकेले मई में, रिलायंस जियो ने लगभग 1.03 मिलियन नए FWA उपयोगकर्ता जोड़े, जबकि भारती एयरटेल के 1.82 लाख उपयोगकर्ता जुड़े।

- अल्ट्रा ब्रॉडबैंड राउटर (UBR) के आंकड़ों को छोड़कर, जियो का मुख्य FWA उपयोगकर्ता आधार 5.9 मिलियन था। यह वृद्धि 5G स्टैंडअलोन (SA) इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित आक्रामक बाजार विस्तार को दर्शाती है।

#### Key Points:-

(i) क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया (CLSA)

की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) की तीसरी तिमाही में जियो का कुल होम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस 1.7 करोड़ (17 मिलियन) तक पहुँच गया, जो एयरटेल के 92 लाख (9.2 मिलियन) से लगभग दोगुना है। जियो के लगभग 70% FWA उपयोगकर्ता भारत के शीर्ष 1,000 शहरों से बाहर स्थित हैं, जो एक महत्वपूर्ण ग्रामीण और टियर 3-4 बाजार पदचिह्न को चिह्नित करता है।

(ii) उत्तर प्रदेश ईस्ट (UP-ईस्ट) टेलीकॉम सर्किल में, जियो एयरफाइबर ने मार्च 2025 तक 87.7% फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) मार्केट शेयर हासिल कर लिया है, जिसमें कुल 4.86 लाख FWA कनेक्शन में से 4.26 लाख सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यह क्षेत्रीय प्रभुत्व अंतिम-मील ब्रॉडबैंड डिलीवरी में जियो की दक्षता को रेखांकित करता है जहाँ फाइबर-टू-द-होम (FTTH) पहुँच अभी भी सीमित है।

2. रिलायंस डिफेंस और अमेरिका स्थित कोस्टल मैकेनिक्स ने महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से रक्षा MRO सुविधा स्थापित करने के लिए साझेदारी की।



जून 2025 में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) की सहायक कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड (RDL) ने महाराष्ट्र में भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये की MRO सुविधा स्थापित करने के लिए संयुक्त

राज्य अमेरिका स्थित कोस्टल मैकेनिक्स कंपनी इंक के साथ एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया।

- इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के सबसे बड़े MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) केंद्रों में से एक बनाना है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन देने के लिए समर्पित है। यह सुविधा अपग्रेड और लाइफ़साइकल सपोर्ट से लेकर एंड-टू-एंड MRO सेवाओं तक रक्षा रखरखाव के पूरे स्पेक्ट्रम को संबोधित करेगी।

- MRO संयुक्त उद्यम महाराष्ट्र के नागपुर (MIHAN) में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट पर आधारित होगा। यह रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और कोस्टल मैकेनिक्स के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) के रूप में काम करेगा, जो घरेलू रक्षा क्षमता को अमेरिकी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ जोड़ेगा।

- आगामी MRO सुविधा भारतीय और वैश्विक रक्षा बाजारों दोनों को सेवा प्रदान करेगी, जो भूमि-आधारित और वायु-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के लिए पूर्ण सर्विसिंग प्रदान करेगी। इसे आयातित घटकों पर निर्भरता कम करने और महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफ़ॉर्म के लिए स्वदेशी समर्थन क्षमताओं को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

#### Key Points:-

(i) अपने कार्यक्षेत्र के तहत, संयुक्त उद्यम जगुआर लड़ाकू विमान, मिकोयान मिग-29 लड़ाकू जेट, भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बोइंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और एल-70 एयर डिफेंस गन सहित प्रमुख रक्षा प्लेटफ़ॉर्मों के लिए MRO समाधान प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विरासत प्रणालियों के आधुनिकीकरण का समर्थन करना भी है।

(ii) यह पहल रक्षा मंत्रालय के तहत भारत के रक्षा

उत्पादन दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में उत्पादन ₹1.46 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो कि FY24 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही, भारत का रक्षा निर्यात ₹24,000 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी भूमिका मजबूत हुई।

(iii) रिलायंस डिफेंस लिमिटेड (RDL) की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसका नेतृत्व CEO राजेश कुमार ढींगरा कर रहे हैं। कंपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और रसद सहायता प्रणालियों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

3. भारत का GST राजस्व जून 2025 में ₹1.85 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा और महाराष्ट्र राज्यों में सबसे आगे है।



जून 2025 में, भारत का माल और सेवा कर (GST) संग्रह ₹1.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें महाराष्ट्र ₹30,553 करोड़ से अधिक का योगदान देकर शीर्ष पर रहा - जो औद्योगिक उत्पादन, वित्त और शहरी खपत में इसके आर्थिक प्रभुत्व को दर्शाता है।

- जून 2025 के लिए कुल सकल GST राजस्व ₹1,84,597 करोड़ रहा, जो जून 2024 में ₹1,73,813 करोड़ से 6.2% साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। यह

वृद्धि आयात GST (+11.4%) में मजबूत प्रदर्शन और मजबूत घरेलू संग्रह (+4.6%) द्वारा समर्थित है।

● महाराष्ट्र जून महीने में सबसे बड़ा GST योगदानकर्ता बनकर उभरा, जिसने ₹30,553 करोड़ का संग्रह किया — जो पिछले वर्ष जून के ₹28,881 करोड़ की तुलना में 6% की वृद्धि है। यह वृद्धि राज्य के वित्त, विनिर्माण, रियल एस्टेट और खुदरा क्षेत्रों द्वारा संचालित है।

#### Key Points:-

(i) कर्नाटक ने ₹13,409 करोड़ (8% वृद्धि) के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, उसके बाद गुजरात ने ₹11,404 करोड़ (सालाना आधार पर स्थिर) और तमिलनाडु ने ₹10,676 करोड़ (4% वृद्धि) के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये राज्य भारत के मजबूत क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों को रेखांकित करते हैं

(ii) नागालैंड में सबसे ज्यादा 71% (₹84 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि त्रिपुरा और बिहार में क्रमशः 18% और 12% की वृद्धि हुई। इस बीच, मणिपुर (-36%), मिज़ोरम (-29%) और उत्तर प्रदेश (-4%) में संकुचन देखा गया, जो विभिन्न क्षेत्रीय माँग को दर्शाता है।

(iii) यह विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार GST डेटा राज्य-स्तरीय आर्थिक गतिविधि के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है - जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों को सबसे आगे दिखाया गया है, जबकि छोटे या कम शहरीकृत क्षेत्रों में असमान सुधार को दर्शाया गया है।

## AWARDS

1. प्रधानमंत्री मोदी को घाना में 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया।



जुलाई 2025 की शुरुआत में, घाना की राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा घाना के स्टार के प्रतिष्ठित अधिकारी से सम्मानित किया गया - जिससे वे 30 वर्षों में यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री बन गए।

● 2 जुलाई, 2025 को राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने PM मोदी को घाना के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना के अधिकारी ग्रेड से सम्मानित किया, जिसमें उनकी "प्रतिष्ठित राजनेता और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व" को मान्यता दी गई।

● PM मोदी ने 1.4 अरब भारतीयों की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया और इसे भारत के युवाओं, सांस्कृतिक परंपराओं तथा भारत-घाना के दीर्घकालिक संबंधों को समर्पित किया; उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का संकल्प लिया।

#### Key Points:-

(i) यह ऐतिहासिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के तीन दशकों में घाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर मिला, जहां पारंपरिक भारतीय परिधान में सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया - जो गहन सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक था।

(ii) यह पुरस्कार समारोह मोदी की पांच देशों की व्यापक यात्रा का हिस्सा है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करना और अर्जेंटीना तथा ब्राजील की यात्राएं भी शामिल हैं, जिससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ेगी।

(iii) यह सम्मान - और इसके स्वागत की गर्मजोशी - भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को रेखांकित करता है और भारत-घाना संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो संस्कृति, लोकतंत्र और विकास में साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

## SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. भारत ने गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।



3-4 जुलाई, 2025 को भारत ने गुरुग्राम के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अध्यक्षों के अपने पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण की थीम के तहत नगरपालिका प्रशासन को मजबूत करने के लिए 500 से अधिक प्रतिनिधि एक साथ आए।

● मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (i-CAT) में आयोजित दो

दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने किया और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया।

● सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक ULB अध्यक्षों ने भाग लिया, जिन्होंने सामान्य परिषद के आचरण, राजकोषीय प्रबंधन, महिला नेतृत्व और 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान देने के लिए यूएलबी को तैयार करने जैसे विषयों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

● लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों से स्थानीय शासन की कार्यकुशलता और नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए संरचित सत्र, प्रश्नकाल और शून्यकाल को संस्थागत बनाने तथा बेहतर संसदीय प्रक्रियाओं की तरह नागरिक परामर्श और जवाबदेही अपनाने का आग्रह किया।

### Key Points:-

(i) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थिरता के माध्यम से ULB क्षमता निर्माण पर प्रकाश डाला, शहरी चुनौती कोष के माध्यम से ₹1 लाख करोड़ के वित्तपोषण की घोषणा की। उन्होंने वैश्विक शहरी मॉडल एक्सचेंजों के लिए स्पेन के साथ भारत के समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया।

(ii) एक सांस्कृतिक संध्या में भारत की विविध विरासत का जश्न मनाया गया, जिसमें पंडित चेतन जोशी द्वारा गंधर्व शैली का वाद्य संगीत, मोंटी शर्मा की मंडली द्वारा ऊर्जावान हरियाणवी लोक नृत्य और संजय शर्मा के कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल थीं - जिन्होंने सांस्कृतिक एकता को रेखांकित किया।

(iii) इंदौर, पुणे, लखनऊ और सूरत के नगर निगमों ने GPS-सक्षम अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर बायोगैस बिजली उत्पादन तक के अभिनव शहर-स्तरीय शासन मॉडल प्रस्तुत किए - जिससे उन्हें शीर्ष प्रदर्शन करने

वाले ULBs के बीच राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई।

## IMPORTANT DAYS

**1. विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 — 2 जुलाई को मनाया गया।**



2 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व खेल पत्रकार दिवस 1924 में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन (AIPS) की स्थापना का सम्मान करता है। यह दिन खेल मीडिया पेशेवरों का जश्न मनाता है और इस वर्ष "चैंपियनिंग फेयर प्ले" थीम के तहत दुनिया भर में नैतिक खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देता है।

- विश्व खेल पत्रकार दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया था, जो 2 जुलाई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान AIPS की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक था। तब से, दुनिया भर में 160 से अधिक सदस्य संगठनों ने खेलों में पत्रकारिता की उत्कृष्टता को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष भाग लिया है।

- 2025 का विषय, "निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना: ईमानदारी और प्रभाव के साथ रिपोर्टिंग", प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफार्मों पर रिपोर्टिंग में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने में खेल पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

## Key Points:-

(i) ऐतिहासिक रूप से, खेल पत्रकारिता की शुरुआत 1800 के दशक की शुरुआत में घुड़दौड़ और मुक्केबाजी के कवरेज के साथ हुई थी, लेकिन 1920 के दशक में इसका काफी विस्तार हुआ - समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठों का 20% तक हिस्सा खेलों के लिए आवंटित किया - जिसके कारण अंततः समर्पित खेल डेस्क की स्थापना हुई।

(ii) वार्षिक समारोहों में पैनल चर्चा, वेबिनार, पुरस्कार समारोह और सोशल मीडिया अभियान शामिल हैं। ये गतिविधियाँ पत्रकारों के पेशेवर अधिकारों को सुदृढ़ करती हैं, नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं और खेल मीडिया व्यवसायियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करती हैं।

## SCIENCE AND TECHNOLOGY

**1. भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट 'उदयगिरि' को शामिल किया।**



1 जुलाई 2025 को, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत अपने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 (उदयगिरि) को कमीशन किया, जिसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा बनाया गया है। यह P17A के तहत दिया गया दूसरा फ्रिगेट है और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

● नए फ्रिगेट INS उदयगिरि का नाम सेवामुक्त INS उदयगिरि के नाम पर रखा गया है, जिसने 1976 से 2007 तक नौसेना में सेवा दी थी। नए पोत में उन्नत स्टेल्थ क्षमताएं, मॉड्यूलर हथियार प्रणाली और बहु-मिशन तत्परता है, जो भारत की समुद्री नौसेना की ताकत को बढ़ाता है।

● प्रोजेक्ट 17A में भारतीय नौसेना के लिए कुल सात उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण शामिल है, जिन्हें नीले पानी के वातावरण में युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है और पारंपरिक और विषम दोनों तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। यह पुराने प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक-क्लास) युद्धपोतों का एक प्रमुख अनुवर्ती है।

● इन जहाजों को वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB), नई दिल्ली द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इन्हें दो भारतीय शिपयार्डों - मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) में बनाया जा रहा है।

#### Key Points:-

(i) उदयगिरि, WDB द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ युद्धपोत है, जो भारत की स्वदेशी नौसैनिक क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के तहत एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से आधुनिक नौसेना के निर्माण पर भारत के फोकस की पुष्टि करती है।

(ii) उदयगिरि का पतवार प्रोजेक्ट 17 के तहत अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 5.44% अधिक लंबाई के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो बेहतर स्थिरता, चुपके और क्षमता प्रदान करता है। यह कम रडार हस्ताक्षर और बेहतर उत्तरजीविता सुविधाओं के साथ गहरे समुद्र में युद्ध भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सुसज्जित है।

(iii) उदयगिरि में संयुक्त डीजल और गैस (CODAG) प्रणोदन प्रणाली, सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार

करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (MRSAM), 76 मिमी और 30 मिमी की नौसेना बंदूकें और स्तरित रक्षा के लिए क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) जैसे उन्नत हथियार शामिल हैं। इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम उच्च प्रतिक्रिया क्षमता के लिए पूरी तरह से स्वचालित है।

#### ENVIRONMENT

1. भारत 2024 में राष्ट्रीय जैव विविधता रिकॉर्ड में 683 जीव प्रजातियां और 433 वनस्पतियां जोड़ेगा।



जून 2025 में, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 'वार्षिक जैव विविधता रिपोर्ट 2024' जारी की, जिसमें भारत के जैव विविधता डेटाबेस में 683 जीव और 433 पुष्प प्रजातियों को जोड़ने की घोषणा की गई।

● इन खोजों को दो राष्ट्रीय जैव विविधता संग्रहों में प्रकाशित किया गया था - भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा "पशु खोज 2024" और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) द्वारा "पौधे खोज 2024", दोनों का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ये रिपोर्ट भारत की पारिस्थितिक संपदा और वैज्ञानिक प्रगति पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण हैं।

● जोड़ी गई 683 जीव प्रजातियों में से 459 नई प्रजातियां थीं, जबकि 224 नए रिकॉर्ड थे - ऐसी

प्रजातियां जो पहले भारत में दर्ज नहीं थीं, लेकिन अन्य जगहों पर जानी जाती थीं। इसमें उभयचर, सरीसृप, मछलियाँ, पक्षी और अकशेरुकी शामिल हैं, जो भारत की ज्ञात पशु विविधता में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाते हैं।

- 433 नए वनस्पतियों में 410 नई पौधों की प्रजातियाँ और 23 नए अंतर-विशिष्ट टैक्सा जैसे कि किस्में और उप-प्रजातियाँ शामिल हैं। इनमें पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय क्षेत्रों और जैव-समृद्ध उष्णकटिबंधीय जंगलों से प्राप्त खोजें शामिल हैं - जो टिकाऊ जैव विविधता प्रबंधन में योगदान देती हैं।

#### Key Points:-

(i) जीवों की खोज में सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक (101 प्रजातियाँ) से आई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (72 प्रजातियाँ) का स्थान रहा। ये खोजें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक समृद्धि की पुष्टि करती हैं - दोनों को IUCN द्वारा वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है।

(ii) पुष्प विविधता के मामले में केरल 58 नए पौधों की खोज के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र में 45 और उत्तराखंड में 40 प्रजातियाँ पाई गईं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट स्थानिक और औषधीय पौधों के अनुसंधान के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है।

(iii) केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के जैव विविधता रिकॉर्ड जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करते हैं और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) के साथ संरेखित हैं, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, बहाली और बढ़ावा देना है।

## Static GK

|                                                            |                                                               |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL)</b>             | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) : कैप्टन जगमोहन (सेवानिवृत्त) | मुख्यालय: मुंबई                       |
| <b>Zoological Survey of India (ZSI)</b>                    | निदेशक : धृति बनर्जी                                          | मुख्यालय : कोलकाता (पश्चिम बंगाल, WB) |
| <b>Office of Principal Scientific Adviser (PSA) to Gol</b> | भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) : अजय कुमार सूद  | मुख्यालय: नई दिल्ली                   |
| <b>Ministry of Coal (MoC)</b>                              | मंत्री: श्री जी. किशन रेड्डी                                  | मुख्यालय: नई दिल्ली                   |
| <b>Tamil Nadu</b>                                          | मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन                                    | राज्यपाल: आर. एन. रवि                 |
| <b>SBI</b>                                                 | अध्यक्ष: चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी                              | मुख्यालय: मुंबई                       |
| <b>IndusInd Bank</b>                                       | CEO : सुमंत कथपालिया                                          | मुख्यालय: मुंबई                       |